

करेंट अफेयर्स

छत्तीसगढ़

(संग्रह)



अप्रैल
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़

➤ अनुच्छेद 21 का उल्लंघन	3
➤ प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों का उद्घाटन किया	4
➤ वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिले	7
➤ बस्तर पण्डुम महोत्सव	8
➤ डोकरा कला	8
➤ बीजापुर में IED बरामद	11
➤ रायपुर में पहला स्वैप किडनी ट्रान्सप्लांट	12
➤ ऑपरेशन कगार	13

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

छत्तीसगढ़

अनुच्छेद 21 का उल्लंघन

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोई भी महिला को कौमार्य परीक्षण के लिये मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जो उसके जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।

मुख्य बिंदु

- मामले की पृष्ठभूमि:
 - ◆ एक याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के लिये कौमार्य परीक्षण की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अवैध संबंध में है।
 - ◆ उन्होंने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।
- कौमार्य परीक्षण पर न्यायालय का रुख:
 - ◆ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी भी महिला को कौमार्य परीक्षण के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।
 - ◆ इसमें कहा गया कि इस तरह का परीक्षण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जो सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
 - कौमार्य परीक्षण की अनुमति देना मौलिक अधिकारों, प्राकृतिक न्याय और महिला की गरिमा का उल्लंघन होगा।
 - ◆ उच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण और अपरिवर्तनीय है।

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

- किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध है।
- अनुच्छेद 21 दो अधिकार प्रदान करता है:
 - ◆ जीवन का अधिकार
 - ◆ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को 'मौलिक अधिकारों का हृदय' बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है।
- यहाँ राज्य में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, विधायिका आदि भी शामिल हैं।
- जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहने के अधिकार के बारे में नहीं है। इसमें गरिमा और अर्थ के साथ पूर्ण जीवन जीने की क्षमता भी शामिल है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



● केस कानून:

- ◆ ए.के. गोपालन केस (1950): 1950 के दशक तक अनुच्छेद 21 का दायरा सीमित था। इस मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने माना कि संविधान में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्द ने अमेरिकी 'उचित प्रक्रिया' के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ब्रिटिश अवधारणा को मूर्त रूप दिया है।
- ◆ **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)**: इस मामले ने गोपालन मामले के फैसले को पलट दिया। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार का दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें कई अधिकार शामिल हैं, जिनमें से कुछ **अनुच्छेद 19** के तहत सन्निहित हैं, इस प्रकार उन्हें 'अतिरिक्त सुरक्षा' दी गई है। न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले कानून को अनुच्छेद 19 के तहत आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिये।
- इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने के लिये कानून के तहत कोई भी प्रक्रिया अनुचित, अविवेकपूर्ण या मनमानी नहीं होनी चाहिये।

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और लोकार्पण किया।

मुख्य बिंदु

- विकास पहल:
 - ◆ प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की।
 - ◆ इन पहलों में वंचितों के लिये आवास, शिक्षा, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढाँचे और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल हैं।
 - ◆ इन परियोजनाओं से न केवल जन सुविधाएँ बढ़ेंगी बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
 - ◆ उन्होंने **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)** के तहत तीन लाख गरीब परिवारों के मकान के सपने पूरे होने पर प्रकाश डाला।
- किसानों को समर्थन देना और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना:
 - ◆ उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों और महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा पिछले वादों को पूरा करना सुनिश्चित किया।
 - ◆ उन्होंने धान किसानों को दो वर्षों के लंबित बोनस के भुगतान तथा **न्यूनतम समर्थन मूल्य** में वृद्धि के साथ धान की खरीद की घोषणा की।
- छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ: “अटल निर्माण वर्ष”
 - ◆ छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री ने 2025 को “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में घोषित किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को समर्पित होगा।
 - ◆ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नव-प्रवर्तित बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ राज्य की समृद्धि के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विस्तार:
 - ◆ उन्होंने दूरदराज़ के आदिवासी क्षेत्रों में संपर्क, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला।
 - ◆ उन्होंने नई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया और छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण का शुभारंभ किया।
 - ◆ उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं को वंचित समुदायों तक पहुँचाने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- छत्तीसगढ़ के ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत बनाना:
 - ◆ प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण-III (9,790 करोड़ रुपये) और छत्तीसगढ़ की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना (15,800 करोड़ रुपये) की आधारशिला रखी।
 - ◆ उन्होंने पावरग्रिड (560 करोड़ रुपये) के तहत तीन विद्युत पारेषण परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं।
 - ◆ इन पहलों का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करना है।
- नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन पहल को आगे बढ़ाना:
 - ◆ प्रधानमंत्री ने कई जिलों में भारत पेट्रोलियम की सिटी गैस वितरण परियोजना (1,285 करोड़ रुपये) का शुभारंभ किया।
 - ◆ उन्होंने ईंधन आपूर्ति दक्षता में सुधार के लिये हिंदुस्तान पेट्रोलियम की विशाख-रायपुर पाइपलाइन परियोजना (2,210 करोड़ रुपये) का भी उद्घाटन किया।
 - ◆ उन्होंने 'प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना' की शुरुआत की, जिससे घरों में सौर ऊर्जा उत्पन्न करने और बिजली की लागत को खत्म करने की सुविधा मिली।
- सड़क और रेलवे संपर्क बढ़ाना:
 - ◆ प्रधानमंत्री ने सात रेलवे परियोजनाओं (108 किमी) की आधारशिला रखी और तीन पूर्ण हो चुकी रेलवे परियोजनाओं (111 किमी) का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत 2,690 करोड़ रुपये है।
 - ◆ उन्होंने जनजातीय और औद्योगिक क्षेत्रों में सम्पर्क सुधारने तथा आर्थिक और सामाजिक एकीकरण को मज़बूत करने के लिये कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
- शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना:
 - ◆ प्रधानमंत्री ने 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया, जिससे शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में वृद्धि हुई।
 - ◆ उन्होंने शिक्षा कार्यक्रमों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिये रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) का शुभारंभ किया।
- ऐतिहासिक उपेक्षा को संबोधित करना और नक्सलवाद का सामना करना:
 - ◆ उन्होंने आदिवासी समुदायों को समर्थन देने के लिये स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत और पीएम जन औषधि केंद्र जैसी पहल पर जोर दिया।
 - ◆ उन्होंने 7,000 आदिवासी गाँवों के उत्थान के लिये 80,000 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए "धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान" की घोषणा की।
 - ◆ उन्होंने "प्रधानमंत्री जनमन योजना" की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2,000 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बस्तियों में बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



प्रधानमंत्री जनमन योजना

- परिचय:
 - ◆ लॉन्च: प्रधानमंत्री जनमन योजना को 15 नवंबर, 2023 को लॉन्च किया गया था, इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
 - ◆ यह पहल भारत के वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री-PVTG विकास मिशन को आगे बढ़ाती है।
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य व्यापक विकास हस्तक्षेप प्रदान करके विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।
- लाभार्थी: इस योजना का लक्ष्य 18 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के 75 PVTG समुदायों को लाभार्थी बनाना है।
- नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो 9 मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है।

पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना

- यह पर्याप्त वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके और इनस्टॉलेशन में सुविधा सुनिश्चित करके सोलर रूफटॉप सिस्टम को अपनाने को बढ़ावा देने के लिये एक केंद्रीय योजना है।
- उद्देश्य: इसका लक्ष्य भारत में एक करोड़ परिवारों को मुफ्त विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराना है, जो रूफटॉप सोलर पैनल वाली बिजली इकाइयाँ स्थापित करना चाहते हैं।
 - ◆ परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी।
- कार्यान्वयन एजेंसियाँ: योजना का क्रियान्वयन दो स्तरों पर किया जाएगा।
 - ◆ राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) द्वारा प्रबंधित।
 - ◆ राज्य स्तर: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) द्वारा प्रबंधित, जो संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों की वितरण उपयोगिताएँ (डिस्कॉम) या विद्युत/ऊर्जा विभाग हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

- मूल रूप से PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) नाम से आरंभ हुई यह योजना 63,000 अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवों में मौजूदा योजनाओं को लागू करने के लिये एक व्यापक योजना है।
 - ◆ धरती आबा का तात्पर्य झारखंड के 19वीं सदी के आदिवासी नेता और उपनिवेशवाद विरोधी प्रतीक बिरसा मुंडा से है।
- इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

- वर्ष 2016 में शुरू की गई PMAY-G का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।
- ◆ यह सुनिश्चित करने के लिये कि सहायता सबसे अधिक पात्र लोगों तक पहुँचे, प्राप्तकर्ताओं का चयन एक कठोर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011**, **ग्राम सभा** की मंजूरी और जियो-टैगिंग शामिल है।
- PMAY-G के अंतर्गत लाभार्थियों को प्राप्त होगा:
 - ◆ **वित्तीय सहायता:** मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों सहित पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपए।
 - ◆ **शौचालयों हेतु अतिरिक्त सहायता:** **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G)** या **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना** या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये 12,000 रुपए।
 - ◆ **रोज़गार सहायता:** आवास निर्माण के लिये **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना** के माध्यम से लाभार्थियों के लिये 90/95 व्यक्ति-दिवस अकुशल मजदूरी रोज़गार का अनिवार्य प्रावधान।
 - ◆ **बुनियादी सुविधाएँ:** प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पानी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और बिजली कनेक्शन तक पहुँच।

वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित ज़िले

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों की संख्या 12 से घटकर छह हो गई है, जो **माओवाद मुक्त राष्ट्र** की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।

मुख्य बिंदु

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में कमी:
 - ◆ वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित ज़िलों की संख्या 12 से घटकर मात्र 6 रह गई है।
 - ◆ केंद्र सरकार **नक्सलवाद** के खिलाफ सख्त रुख और केंद्रित विकास के माध्यम से **भारत को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने** के लिये प्रतिबद्ध है।
- तीव्र माओवादी विरोधी अभियान:
 - ◆ **छत्तीसगढ़ में उग्रवाद विरोधी अभियानों में तेजी** देखी गई है।
 - ◆ वर्ष 2024 में 219 माओवादियों का सफाया किया गया, जबकि 2023 में 22 और 2022 में 30 माओवादियों का सफाया किया गया, जो आतंकवाद विरोधी प्रयासों में तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।
 - ◆ **बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागाँव और सुकमा** सहित प्रमुख माओवादी गढ़ उग्रवाद का केंद्र बने हुए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ माओवादियों के ठिकानों और किलेबंदी को ध्वस्त करने के लिये “लाल गलियारे” में हजारों सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।
- सरकार की बहुआयामी रणनीति:
 - ◆ केंद्र सरकार का लक्ष्य निरंतर सैन्य कार्रवाई और सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम से 31 मार्च 2026 तक माओवाद का उन्मूलन करना है।
 - ◆ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और अन्य विकासात्मक पहलों सहित बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।

बस्तर पण्डुम महोत्सव

चर्चा में क्यों ?

- केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पण्डुम महोत्सव को संबोधित किया, जिसमें जनजातीय विरासत का उत्सव मनाया गया तथा नक्सलवाद के उन्मूलन और क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिये चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य बिंदु

- सांस्कृतिक पहचान और बस्तर पण्डुम:
 - ◆ छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र अपनी आदिवासी संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाजों और विविध आदिवासी व्यंजनों के लिये जाना जाता है।
 - बस्तर की इस समृद्ध आदिवासी कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करने और इसे देश-विदेश के सामने लाने के लिये बस्तर पण्डुम का आयोजन किया गया।
 - ◆ इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी नृत्य, लोकगीत, आदिवासी नाटक, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प और व्यंजन सहित सात विधाओं में प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।
 - अगले वर्ष इसे बारह श्रेणियों में मनाया जाएगा और देश भर से आदिवासी लोग इसमें भाग लेंगे।
- नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई:
 - ◆ सरकार का लक्ष्य: मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत।
 - ◆ ग्राम प्रोत्साहन योजना: नक्सल मुक्त घोषित गाँवों को विकास निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे।
- शासन एवं विकास पहल:
 - ◆ जनजातीय पहचान और इतिहास को बढ़ावा देना: जनजातीय उत्पादों के लिये जीआई टैगिंग और “वोकल फॉर लोकल” पहल।
 - ◆ जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की राष्ट्रीय मान्यता:
 - बस्तर के वीर गुण्डाधुर का सम्मान।
 - बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय गौरव दिवस घोषित किया गया।
 - 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में 150वीं वर्षगांठ मनाई गई।

डोकरा कला

चर्चा में क्यों ?

बैंकॉक की अपनी यात्रा के दौरान, भारत के प्रधानमंत्री ने थाई प्रधानमंत्री श्रेष्ठा थाविसिन और उनकी पत्नी को पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प भेंट किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूप
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- उपहारों में एक डोकरा पीतल की मयूर नाव थी जिस पर एक आदिवासी सवार बना हुआ था, जो छत्तीसगढ़ की आदिवासी धातु कलाकृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

- डोकरा कला के बारे में:
 - ◆ यह प्राचीन बेल मेटल शिल्प का एक रूप है, जिसका उपयोग झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में रहने वाले ओझा धातु कारीगरों द्वारा किया जाता है।
 - इस कारीगर समुदाय की शैली और कारीगरी विभिन्न राज्यों में भिन्न होती है।
 - ◆ सदियों पुरानी खोई हुई मोम की ढलाई पद्धति का उपयोग करके तैयार की गई यह मूर्ति छत्तीसगढ़ की जटिल आदिवासी कलात्मकता को दर्शाती है। हर टुकड़ा अद्वितीय है और सावधानीपूर्वक हस्तनिर्मित है।
 - ◆ मोहनजोदड़ो (हड़प्पा सभ्यता) की नृत्यांगना अब तक ज्ञात सबसे प्रारंभिक डोकरा कलाकृतियों में से एक है।
- प्रतीकात्मकता और सौंदर्यात्मक आकर्षण:
 - ◆ जटिल डिज़ाइन और ज्वलंत लाख की नक्काशी से सुसज्जित मोर के आकार की यह नाव सुंदरता, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गहराई का प्रतीक है।
 - ◆ नाव को धीरे-धीरे चलाते हुए जनजातीय आकृति मानव-प्रकृति सामंजस्य का सार प्रस्तुत करती है, जो डोकरा कला का एक केंद्रीय रूपांकन है।
 - पीतल से निर्मित यह मूर्ति समय के साथ स्वाभाविक रूप से समृद्ध पट्टिका (पेटिना) प्राप्त कर लेती है, जिससे इसका प्राचीन आकर्षण और ऐतिहासिक आकर्षण बढ़ जाता है।
 - ◆ यह मात्र एक सजावटी वस्तु नहीं है, बल्कि यह भारत की जनजातीय विरासत का सम्मान करती है तथा सादगी, कलात्मक अभिव्यक्ति और प्रकृति के साथ गहन संबंध का मिश्रण दर्शाती है।
- सोना चढ़ाया बाघ आकृति कफ़लिक:
 - ◆ भारत के प्रधानमंत्री ने थाई प्रधानमंत्री की पत्नी को सोने की परत चढ़ी एक जोड़ी कफ़लिक भेंट की, जिस पर मोतियों से सुसज्जित एक जटिल बाघ आकृति बनी हुई थी।
 - बाघ का आकर्षक चेहरा शक्ति, अधिकार और शाही आकर्षण का प्रतीक है।
 - ◆ राजस्थान और गुजरात का एक पारंपरिक मीनाकारी शिल्प डिज़ाइन में जीवंत रंग और कलात्मकता जोड़ता है।

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत की सक्रिय भूमिका:

- भारत के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में आयोजित बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहाँ उन्होंने बिम्सटेक बैंकॉक विज्ञान 2030 और बिम्सटेक समुद्री परिवहन समझौते को अपनाने की सलाहना की।
- उन्होंने क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार, तकनीकी नवाचार और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिये भारत की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





बिम्सटेक

बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल

संख्या: 7

महत्त्व: दुनिया की 22% आबादी की मेलजामी करता है, समस्त घरेलू उत्पाद का 3.8 ट्रिलियन है

महत्त्व: 6 जून 1997 (बैकाल शोधना)

संघिवालय: ढाका, बांग्लादेश



भूटान

- भूटान दुनिया का सबसे बड़ा पारदर्शी देश है।
- भूटान की राजधानी थम्पू में स्थित है।
- भूटान की राजधानी थम्पू में स्थित है।
- भूटान की राजधानी थम्पू में स्थित है।

नेपाल

- नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है।
- नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है।
- नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है।
- नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है।

भारत

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है।
- भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।
- भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।
- भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।

बांग्लादेश

- बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है।
- बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है।
- बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है।
- बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है।

श्रीलंका

- श्रीलंका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है।
- श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्थित है।
- श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्थित है।
- श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्थित है।

मलदीव

- मलदीव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है।
- मलदीव की राजधानी माले में स्थित है।
- मलदीव की राजधानी माले में स्थित है।
- मलदीव की राजधानी माले में स्थित है।

थाईलैंड

- थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है।
- थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित है।
- थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित है।
- थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

बीजापुर में IED बरामद

चर्चा में क्यों ?

सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में माओवादियों द्वारा लगाए गए पाँच इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद किये।

मुख्य बिंदु

● IED का पता लगाना:

- ◆ छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने बीजापुर ज़िले के मनकेली गाँव के पास पाँच IED बरामद किये।
- ◆ टीम क्षेत्र पर कब्ज़ा करने और बारूदी सुरंग हटाने का अभियान चला रही थी, तभी उन्हें विस्फोटक मिले।
- बस्तर क्षेत्र में माओवादी हमलों का स्वरूप:
 - ◆ माओवादी अक्सर बस्तर क्षेत्र के आंतरिक इलाकों में जंगल की सड़कों और कच्ची पगडंडियों पर IED लगाते हैं, जिसमें बीजापुर और छह अन्य ज़िले शामिल हैं।
 - ◆ ये जाल अक्सर गश्त के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, लेकिन कई मामलों में नागरिक भी हताहत हो जाते हैं।

इंप्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण

- ◆ इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) एक स्वदेशी बम है, जिसे लक्ष्यों को नष्ट करने या अक्षम करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिसका उपयोग आमतौर पर अपराधियों, आतंकवादियों और विद्रोहियों द्वारा विभिन्न रूपों में किया जाता है।
- IED को कई तरीकों से पहुँचाया जा सकता है, जिसमें वाहनों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा रखा जाना या सड़क के किनारे छिपाया जाना शामिल है तथा वर्ष 2003 में शुरू हुए इराक युद्ध के दौरान इसे प्रमुखता मिली।

माओवाद

- परिचय:
 - ◆ माओवादी, जिन्हें वामपंथी उग्रवादी (LWE) या नक्सलवादी भी कहा जाता है, भारत में माओवादी विचारधारा पर आधारित एक समूह है, जो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने की वकालत करता है।
- माओवादी विचारधारा:
 - ◆ माओवादी विचारधारा का केंद्रीय विषय राज्य सत्ता पर कब्ज़ा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग करना है।
 - माओवादी उग्रवाद सिद्धांत के अनुसार, 'हथियार रखने पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता'।
- भारतीय माओवादी:
 - ◆ भारत में सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) है जिसका गठन वर्ष 2004 में हुआ था।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ CPI (माओवादी) और उसके अग्रणी संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया।
- ◆ फ्रंट ऑर्गनाइजेशन मूल माओवादी पार्टी की शाखाएँ हैं, जो कानूनी उत्तरदायित्व से बचने के लिये अलग अस्तित्व का दावा करती हैं।

रायपुर में पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट

चर्चा में क्यों ?

एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी पेयर्ड डोनेशन (KPD) पूरा किया है, जिससे वह न केवल नए एम्स संस्थानों में यह प्रक्रिया करने वाला पहला, बल्कि छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अस्पताल भी बन गया है जिसने यह उन्नत और जीवन रक्षक प्रक्रिया की है।

मुख्य बिंदु

- गुर्दा चिकित्सा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि:
 - ◆ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शन में एम्स रायपुर ने अपना पहला स्वैप किडनी प्रत्यारोपण किया।
 - ◆ मंत्रालय ने इसे अंतिम चरण के किडनी की बीमारी (ESRD) के रोगियों के लिये उन्नत उपचार तक पहुँच का विस्तार करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।
 - ◆ स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट (किडनी पेयर डोनेशन) में, दो मरीज-दाता जोड़े किडनी का आदान-प्रदान करते हैं, जब रक्त समूह की असंगति के कारण प्रत्यक्ष दान संभव नहीं होता है।
- एम्स रायपुर: उभरता हुआ क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र
 - ◆ एम्स रायपुर मध्य भारत में अंग प्रत्यारोपण में अग्रणी बनकर उभरा है।
 - ◆ यह नए एम्स में मृतक दाता अंग दान और बाल चिकित्सा किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने वाला पहला एम्स था।
 - ◆ अब तक अस्पताल में किये गये 54 किडनी प्रत्यारोपणों में 95% ट्रांसप्लांट सफल रहे हैं और 97% मरीज उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।
- राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण क्षमता को बढ़ावा देना:
 - ◆ राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के अनुसार, स्वैप प्रत्यारोपण से कुल किडनी प्रत्यारोपण में 15% तक की वृद्धि हो सकती है।
 - ◆ NOTTO ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्वैप ट्रांसप्लांट कार्यक्रम लागू करने की सलाह दी है।
 - ◆ इसने भारत भर में इन जीवनरक्षक सर्जरी को सुव्यवस्थित और विस्तारित करने के लिये “एक राष्ट्र, एक स्वैप प्रत्यारोपण” नीति शुरू करने की भी योजना बनाई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

ऑपरेशन कगार

चर्चा में क्यों ?

बढ़ती हिंसा और विवादास्पद सुरक्षा अभियानों की पृष्ठभूमि में, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के ऑपरेशन कगार पर चिंता जताई है।

- छत्तीसगढ़ में **माओवादी** विद्रोहियों को खत्म करने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान की कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से आदिवासियों और युवाओं की हत्या के आरोप लगे हैं।

टिप्पणी:

- केंद्रीय गृहमंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नक्सलवाद के समूल खात्मे के लिये प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाये, ताकि किसी भी नागरिक को इसकी वजह से अपने प्राण न गँवाने पड़ें।

मुख्य बिंदु

- ऑपरेशन कगार के बारे में:
 - ◆ गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए ऑपरेशन कगार का उद्देश्य **नक्सलियों का उन्मूलन करना** और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है।
 - ◆ इस अभियान में उन माओवादियों को भारी क्षति हुई है जिन्होंने सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है।
- साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार, 2025 के पहले तीन महीनों में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा 140 से अधिक माओवादियों को मार गिराया गया।
 - ◆ यह आँकड़ा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में होने वाली कुल मृत्यु संख्या के आधे से भी अधिक है, जोकि 235 है।
- आदिवासियों और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव
 - ◆ सरकार का दावा है कि ऑपरेशन कगार का उद्देश्य शांति लाना है, लेकिन इसके चलते स्थानीय समुदायों, विशेषकर **आदिवासी** आबादी पर गहरा असर पड़ा है।
 - ◆ कई आदिवासी गोलीबारी में फँस गए हैं और सरकार के आक्रामक रुख से स्थानीय आक्रोश और बढ़ गया है।
 - ◆ नक्सलियों और सुरक्षा बलों दोनों की ओर से हिंसा में वृद्धि ने जनजातीय समुदायों और सरकार के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे केवल सैन्य कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाए उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को दूर करने की मांग बढ़ गई है।

नक्सलवाद

- परिचय: नक्सलवाद, **माओवादी विचारधारा** से प्रेरित वामपंथी उग्रवाद का एक रूप है, जो सशस्त्र विद्रोह (हिंसा और गुरिल्ला युद्ध) के माध्यम से राज्य को समाप्त करने का प्रयास करता है।
 - ◆ नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई है, जहाँ वर्ष 1967 में शोषक ज़मींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह हुआ था।
 - ◆ इसके बाद से यह एक जटिल उग्रवाद के रूप में विकसित हो गया है, जो भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर रहा है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- **भारतीय माओवादी: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)** भारत का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी समूह है। इसका गठन दो प्रमुख माओवादी गुटों: CPI (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वार और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के विलय से हुआ था।
 - ◆ CPI (माओवादी) और उसके संगठनों को **UAPA, 1967** के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- **भौगोलिक विस्तार:** नक्सल आंदोलन “रेड कॉरिडोर” में सबसे अधिक सक्रिय है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार सहित कई भारतीय राज्यों के हिस्सों में फैला हुआ है।
- **नक्सलवाद के कारण:**
 - ◆ **भूमिहीनता और शोषण:** असमान भूमि वितरण और जमींदारों, साहूकारों एवं बिचौलियों द्वारा शोषणकारी प्रथाओं के कारण ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष बढ़ा और नक्सलवाद को बढ़ावा मिला।
 - ◆ **गरीबी और अल्प विकास:** नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोग उग्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं।
 - ◆ **जनजातीय अलगाव:** उचित पुनर्वास के बिना औद्योगिक और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापन से राज्य के प्रति गुस्सा और अविश्वास बढ़ता है, जिसके कारण कई लोग नक्सलवादी आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं।
 - ◆ **राज्य की उपेक्षा और हिंसा:** सरकारी तंत्र अनुपस्थिति, बुनियादी सेवाओं की कमी तथा हिरासत में मृत्यु सहित पुलिस की ज्यादतियों के मामलों ने शिकायतों को और बढ़ा दिया है, जिससे नक्सली विद्रोह को मजबूती मिली है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

वामपंथी उग्रवाद

परिचय

- उत्पत्ति: वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में विद्रोह
- उद्देश्य: क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव

विचारधारा

- सशस्त्र क्रांति (हिंसा और गुरिल्ला पद्धति) के माध्यम से केंद्र सरकार का विरोध
- माओवादी सिद्धांतों पर आधारित साम्यवादी राज्य की स्थापना

ज़िम्मेदार कारक

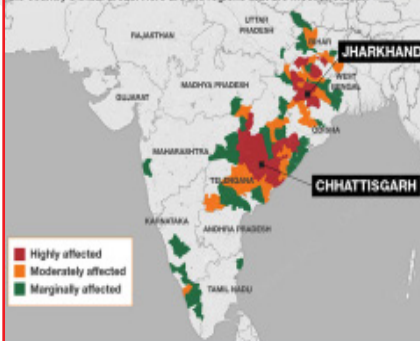
- विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों के कारण जनजातीय आबादी का बहुद स्तरीय विस्थापन
- आदिवासी असंतोष; वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 जनजातियों को वन संसाधनों की कटाई करने से रोकता है
- निर्धनता और स्थायी साधनों की कमी; नक्सली आंदोलन में शामिल होने के लिये प्रेरक कारक
- प्रभावी शासन का अभाव; नक्सलवाद के विरुद्ध अपर्याप्त तकनीकी खुफिया जानकारी

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य

- रेड कॉरिडोर: गंभीर नक्सलवाद-माओवादी विद्रोह का अनुभव
- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल

A map of India's Maoist conflict

A crackdown on Maoist rebels has led to a rise in the number of casualties in the country's tribal areas. Here are the regions that are most affected.



वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने हेतु सरकारी पहलें

- वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015
- SAMADHAN सिद्धांत
- 9- स्मार्ट लीडरशिप
- A- एग्जिबिट स्ट्रेटेजी
- M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग
- A- एक्शनबल इंटेलिजेंस
- D- डैशबोर्ड-बेस्ड KPIs (Key Performance Indicators) और KRAs (Key Result Areas)
- H- हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी
- A- एक्शन प्लान फॉर ड्रव थिएटर
- N- नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग
- सार्वजनिक अवसरचना और सेवाओं में विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)
- ऑपरेशन ग्रीन हंट
- ग्रेहाउंड (आंध्र प्रदेश का इलीट कमांडो फोर्स)
- बस्तरिया बटालियन (छत्तीसगढ़ में स्थानीय नियुक्तियों जो भाषा और इलाके से परिचित हैं, जिससे खुफिया जानकारी एकत्रित की जा सके और ऑपरेशन किये जा सकें)

नक्सलवाद का सामना- बंदोपाध्याय समिति (वर्ष 2006)

- इसमें जनजातियों के प्रति आर्थिक, सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव एवं शासन की अपर्याप्त नीतियों पर प्रकाश डाला गया
- इसमें आदिवासियों के लिये भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की सिफारिश की गई



Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :